to (c) The package for revival of IDPL approved by BIFR on 10.2.1994 was implemented w.e.f. 1.4.1994. The same had, however, failed in the first year of its operation as IDPL could not achieve the targetted levels of production, sales and profitability in the year 1994-95. IDPL management thereafter proposed the modifications in the revival package. The modified package as proposed by IDPL was referred to BIFR for consideration. The BIFR appointed an Operating Agency for undertaking a techno-economic viability study for long term revival measures for IDPL. The reports received in this regard are being processed from all the relevant aspects after giving due considerations to the views/comments of the other concerned Departments and quarters. The matter is still under consideration.

Cancellation of DAP import Contracts

1405. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times dated the 18th November, 1998 captioned "DAP import contracts cancelled by HLCL due to inconsistent policies" especially with regard to fixation of prices for DAP, complexed subsidy component and also its disbursal method followed by Central Government;

(b) whether Fertilizer Industry as well as fertilizers Association of India have blamed Government for cancellation of DAP import contracts worth 1.25 lakh tonnes, leading to shortage of Phosphates in the Kharif season; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto and the remedial steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K.PATEL): (a) to (c) DAP is a decontrolled fertilizer. The demand and supply of DAP is regulated by the market forces depending upon the rates of concession and Maximum Ratail Price (MRP) fixed by the Government under the Concession Scheme. No shortages were experienced during the Kharif season. For Rabi '98-99, the Government decided first In August '98 to fix the rates of concessions alone and leave MRPs in respect of DAP and other decontrolled fertilizers to the market forces. But the policy was rolled back in September '98 in the interest of the farmers as the market determined MRPs of DAP were reported to settle at much higher levels than anticipated . The change of policy resulted in cancellation of nearly 1.30 lakh MTs of.

Losses of IPCL

1406. SHRI RAJNATH SINGH SURYA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that IPCL is recording losses during the current year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to arrest the decline?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (Shri A.K. PATEL): (a) to (c) Yes, Sir. Indian Petrochemicals Corporation Limited (IPCL) incurred a net loss of Rs. 23.81 crore in the first half of the FISCAL year 1998-99. The loss was mainly on account of depressed prices of Polymers products. The company has already initiated several steps including increase in the volumes of production, strict control on costs and higher capacity utilisation.

उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकता

1407. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता है;

(ख) घरेलू उत्पादन से यह मांग किस हद तक पूरी हो सकेगी; और

(ग) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किए जाने की संभावना है और इस अवधि के दौरान इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल:): (क) यूरिया एक मात्र उर्वरक है जिस पर भारत सरकार का मूल्य, वितरण तथा संचलन नियंत्रण है। प्रत्येक मौसम शुरू होने से पूर्व इसकी मांग का राज्यवार आकलन किया जाता है। फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरक नियंत्रणमुक्त है। चूंकि इनकी आपूर्ति और मांग रियायत योजना के मानदंडों के अन्तर्गत बाजार द्वारा नियंत्रित की जाती है, अतः इनकी आवश्यकता का कोई औपचारिक आंकलन नहीं किया जाता । वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के लिये यूरिया तथा नियंत्रणमुक्त प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी के लिये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) खरीफ, 98 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिये यूरिया की सम्पूर्ण आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया गया था। रबी 1998-99 के दौरान भी, सम्पूर्ण आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जायेगा। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के सम्बन्ध में इस प्रकार के ब्यौरे विभाग द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) यूरिया के आयात सरणीबद्ध हैं और सरकारी खाते में किये जाते हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान 5.56 लाख मी० टन० यूरिया का आयात किया गया है। विदेशी मुद्रा में 53.54 मिलियन डालर का कुल व्यय किया गया है। वर्ष 1999-2000 के लिये आयातों की आवश्यकता का आंकलन चल रहे रबी मौसम के दौरान यूरिया खपत की प्रवृत्ति सुनिश्चित हो जाने के बाद किया जायेगा।

डी ए पी और एम ओ पी का आयात निजी व्यवसाय खाते में किया जाता है। इसलिये वर्ष 1999-2000 के दौरान सम्भावित आयातों का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान 30.11.1998 तक 12.47 लाख टन एमओपी तथा 17.04 लाख टन डी ए पी का आयात किया गया है। इनके आयातों पर हुये विदेशी मुद्रा व्यय के सम्बन्ध में सूचना विभाग के पास नहीं है।

विवरण

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डी०ए०पी०) तथा म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की मांग

(लाख टन में)

उत्पाद	1997-98		1998-99	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
यूरिया*	21.20	27.00	22.25	27.30
डी ए पी**	3.50	6.00	4.00	6.00
एम ओ पी**	0.60	0.90	0.60	0.90

*अनुमानित मांग

**राज्यों द्वारा सम्भावित मांग

Viability of the sick fertilizer Units/Plants

1408. SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government had asked for a report on the viability of each of the sick fertilizer units/plants, both in the public and private sectors in the country;